बाल भिक्षुकों की होगी जांच : चाकणक

▪ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष ने पत्र परिषद में दी जानकारी

ब्यूरो। वर्धा. सड़क, चौक या मंदिर के बाहर बड़े प्रमाण में महिलाएं, छोटे बच्चे भीख मांगते हुए नजर आते हैं। यह मानवी तस्करी से जुड़ा हो सकता है। जिससे इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी कल से ही जांच शुरू कर दी जाएगी, ऐसा आश्वासन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकणकर ने दिया। वे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में पत्र बोल रही थीं। इस समय राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे, जिलाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन आदि उपस्थित थे। रूपाली चाकणकर ने आगे कहा कि जिले में जिलाधिकारी राहुल कर्डिले, एसपी नुरूल हसन तथा सीओ रोहन घुगे तीनों युवा वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं। युवाओं के प्रश्न रख रहे हैं। उत्साह से काम कर रहे हैं। परिणामस्वरूप जो प्रश्न अन्य जिलों में हमें बड़े प्रमाण में दिखाई दिए प्रश्न आज वर्धा जिले में काफी प्रमाण में हैं। जिले में महिला व बाल की सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न उप चलाए जा रहे हैं। जिसमें स्वच्छता मुद्दा अहम होकर इस पर काम है। उन्होंने आगे कहा कि, राज्य मह आयोग द्वारा राज्य में समीक्षा बैठक जा रही है।

शेष पेज 14

समिति नहीं बनाई तो होगी कार्रवाइ

चेतावनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने लिया विविध विभागों के कामों का जायजा

लोकमत समाचार सेवा

वर्धा : महिलाओं की समस्याओं और सुरक्षा के लिहाज से अनेक कार्यालयों में अब तक इंटरनल ग्रीवेंस रिड्रेसेल कमेटी (आईजीआरसी) नहीं बनी है. 7 से 15 दिन के भीतर कार्यालयों में समिति नहीं बनाने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने दी है. चाकनकर ने विकास भवन में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक ली.

बैठक में जिलाधिकारी राहुल कर्डिले, पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन, आयोग की सदस्य आभा पांडे, वर्धा जि.प. के सीईओ रोहन घुगे, निवासी उप जिलाधिकारी अर्चना मोरे, विधि सेवा प्राधिकरण के देशमुख, महिला व बाल विकास विभागीय उपायुक्त अपर्णा कोल्हे, जिला महिला व बाल विकास अधिकारी प्रशांत विधाते मौजूद थे.

बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने जिला स्तर पर महिलाओं एवं बालकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली. साथ ही आवश्यक निर्देश दिए. बैठक में नागरिकों के लिए शुरु की गई. शासन की सेवादूत योजना एवं बचत समूहों को मार्केट उपलब्ध करानेवाली वर्धिनी ब्रांड की सराहना की. पुलिस विभाग की ओर से मिसिंग केस पर होनेवाले काम को भी सराहा. चाकनकर ने कहा कि कार्यालयों में महिलाओं की समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्गत शिकायत निवारण समिति का काम संतोषजनक नहीं है. अर्धसरकारी, निजी कार्यालयों में अल्प समितियां बनी हैं.

कामगार कार्यालयों से इसकी रिपोर्ट आठ दिन के भीतर चाकनकर ने मांगी है. साथ ही जिले में महिलाओं की कौंसिलिंग के लिए बनाए गए केंद्रों को तत्काल पुन: शुरु करने के निर्देश भी उन्होंने दिए.

विकास भवन में आयोजित बैठक में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर का स्वागत करते जिलाधिकारी राहुल कर्डिले साथ में एसपी नुरुल हसन.

चाकनकर ने किए सेवाग्राम आश्रम के दर्शन

वर्धा : वर्धा के दौरे पर आई राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने सेवाग्राम आश्रम के दर्शन किए. आश्रम में उन्होंने सर्वधर्म प्रार्थना भी की. आश्रम में उन्होंने सभी कुटियों का ऐतिहासक महत्व उसके निर्माण के उद्देश्य इत्यादि की जानकारी आश्रमवासियों से ली. इस दौरान रुपाली चाकनकर ने कहा कि देश की आजादी के लिए लड़नेवाले महात्मा गांधी का आश्रम आज भी उतनी ही सादगी से परिपूर्ण है. गांधीजी ने देश को यही शिक्षा दी कि सादगी और हमेशा जमीन से जुड़े रहकर समाज के लिए काम करना चाहिए. आश्रम में आने के बाद सेवा की एक अद्‌भुत प्रेरणा और ऊर्जा शरीर को मिलती है.

आश्रम में जानकारी लेती हुई चा

पत्र परिषद में की अधिकारियों की सरा

वर्धा : वर्धा के दौरे पर आई राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रुपाली चाकनकर ने आज दोपहर में जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र परिषद बुलाई थी. पत्र परिषद में चाकनकर ने वर्धा के अधिकारियों की युवा टीम और उनके कार्यों की सराहना की. चाकनकर ने कहा कि युवा टीम बेहतर काम कर रही है. गुमशुदगी के केस भी कम ही हैं. महिलाओं से संबंधित अत्याचार और अपराध में कमी आई है. वर्धिनी के माध्यम से बचत समूहों के लिए भी जिला प्रशासन की टीम बेहतर काम कर रही है. जिले में बाल विवाह की संख्या कम है, जो बाल विवाह होने थे, उन्हें प्रशासन ने तत्काल कदम उठाकर रोक दिया है. पत्र परिषद में चाकनकर ने बताया कि सुरक्षा के लिए अंतर्गत शिकायत निवारण स कार्यालयों में 150 में से 133 जगहों पर बनी है, जबकि में केवल 27 स्थानों पर समितियां बनी हैं. 7 से 15 समितियां नहीं बनाने पर उन पर कार्रवाई की जाएगी यदि किसी धार्मिक स्थल पर होता है, तो संबंधित द दर्ज किया जाएगा. पत्र परिषद में जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक नुरुल हसन, जिला परिषद के सीई जिला सूचना अधिकारी मंगेश वरकड सहित अन्य उ

धोरणात अपेक्षित असलेल्या सुविधा महिलांना मिळाल्या पाहिजे : रुपाली चाकण

*** राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षांनी घेतला आढावा**
*** बालविवाह थांबविण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश**
*** महिला, मुलींसाठी स्वतंत्र, स्वच्छ शौचालये असावीत**

वर्धा : राज्यात महिलांच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक महिला धोरण आहे. या धोरणात महिलांच्या सक्षमिकरणासाठी विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. धोरणातील तरतुदींप्रमाणे महिलांना सुविधा मिळाल्या पाहिजे. सर्वच क्षेत्रात त्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळावी. त्यासाठी याविषयावर काम करणाऱ्या सर्व विभागांनी सामुहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले. विकास भवन येथे श्रीमती चाकणकर यांनी महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रम आदींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला अध्यक्षांसह आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, पोलिस अधीक्षक नूरूल हसन, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव विवेक देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, महिला व बालविकासच्या विभागीय उपायुक्त अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रशांत विधाते उपस्थित होते.

यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी महिलांसाठी योजना, उपक्रम राबवित असलेल्या महिला व बालविकास विभाग, आरोग्य, कामगार, शिक्षण, पोलिस, कौशल्य विकास, परिवहन आदी विभागांचा बाबनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. शासकीय, निमशासकीय, खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गत तक्रार निवारण समिती असणे गरजेचे आहे. ज्या आस्थापनांनी समित्या स्थापन केल्या नसतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करा. येत्या काही दिवसात सर्व ठिकाणी समित्या स्थापन करून तसा अहवाल आयोगास सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधित विभागांना दिले. बालविवाह अत्यंत वाईट गोष्ट आहे. बालविवाह होऊच नये यासाठी महिला व बालविकाससह पोलिस विभागाने अधिक काम करणे आवश्यक आहे. बालविवाह आढळल्यास विवाहात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करा. तुळशी विवाह व अक्षय तृतीयेच्या दिवशी काही ठिकाणी बालविवाह होतात, ते होणार नाही यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाव्या. अवैध गर्भपातावर प्रतिबंध घालून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी कायदा करण्यात आला आहे. त्यानंतरही गर्भपात होत असल्याचे दिसते. यासाठी विशेष मोहिम राबवा, संबंधितांवर कठोर कारवाई करा, असे निर्देश देखील श्रीमती चाकणकर यांनी दिले.

वर्धा जिल्ह्यात केवळ महिलांसाठी शासकीय वसतीगृह नसल्याने तसा प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. बसस्थानकांवर असलेली शौचालये वापरण्यासाठी विनामुल्य आहे, असे असतांना महिलांकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी येतात, तसे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जावी. गर्दीच्या ठिकाणी केवळ महिलांसाठी शौचालये असावीत. शाळांमध्ये विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र आणि पुरेसे पाणी असलेले शौचालये असावीत. जेथे शौचालये नाहीत तेथे प्रस्तावित करण्यात यावी. महिलांच्या कल्याणासाठी प्रशासनाने सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने काम करावे. राज्यात 35 टक्के महिला 'वर्किंग वुमन' आहे. त्या घराबाहेर पडत आवश्यक सुविधा कर्तव्य आहे, या विभागाने काम करा वास्तव्यामुळे व ओळख प्राप्त अत्याचारांच्या जिल्ह्याला गालबं वर्धेत महिला, मु भेडसावणारे प्र चांगली बाब अ श्रीमती चाकणकर सुरुवातीस जिल्हा कर्डिले यांनी अ चाकणकर यांचे स